बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 112 ● नई दिल्ली ● बुधवार 11 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

बवाना में कारोबारी की हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ, सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी

नई दिल्ली ।दिल्ली के बवाना इलाके में सोमवार को हुई कारोबारी वैभव गांधी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के माध्यम से गैंग ने इस हत्या को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। गैंग ने स्पष्ट किया है कि यह हत्या किसी लूटपाट के इरादे से नहीं की गई थी, बल्कि रंगदारी मांगने के मामले में कारोबारी के बीच में आने के कारण हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि कारोबारी वैभव गांधी ने रंगदारी मांगने के दौरान हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। इसी कारण उन्हें निशाना बनाया गया। गैंग ने आगे चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में जो भी इस तरह के मामलों में बीच में आएगा, उसे भी इसी अंजाम का सामना करना पड़ेगा।

पीएम मोदी डिग्री मामला: केवल सनसनी फैलाने का प्रयास; डीयू का दो टूक जवाब; दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया 3 हफ्ते का समय

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़ी जानकारी के खुलासे को लेकर चल रहे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को बड़ी राहत दी।

कोर्ट ने अपील दाखिल करने में हुई देरी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए विश्वविद्यालय को तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा जैसा कि प्रार्थना की गई है, देरी माफ करने से संबंधित आवेदन पर आपत्ति दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि इस पूरे मामले में कुछ भी ठोस नहीं है और इसे केवल सनसनी फैलाने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने अपील में हुई देरी के साथ-साथ मामले के गुण-दोष पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील ने कोर्ट को बताया कि करीब ढाई महीने बीत जाने के बावजूद डीयू ने देरी पर आपत्ति दाखिल नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह देरी केवल 15 से 45 दिनों की है, जिसे अदालत

आसानी से माफ कर सकती है। वकील ने यह भी मांग की कि यदि दिल्ली विश्वविद्यालय मुख्य अपील पर जवाब देना चाहता है, तो कोर्ट औपचारिक नोटिस जारी करे। इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा नोटिस जारी करना सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए नहीं हो सकता। यह अपील दिल्ली हाईकोर्ट के उस एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसने 25 अगस्त 2025 को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। अपीलकर्ताओं में आरटीआई कार्यकर्ता नीरज, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद शामिल हैं। गौरतलब है कि एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा था कि केवल सार्वजनिक पद पर होने के कारण किसी व्यक्ति की सभी व्यक्तिगत जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं। कोर्ट ने साफ कहा कि आरटीआई कानून का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है, न कि सनसनी के लिए सामग्री उपलब्ध कराना। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि यदि किसी सार्वजनिक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होती, तो स्थिति अलग हो सकती थी। इसी आधार पर सीआईसी के रुख को पूरी तरह गलत बताया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी फैसले में सीआईसी के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कक्षा 10 और 12 के रिकॉर्ड सीबीएसई से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

India-US Deal पर खरगे ने पूछे तीखे सवाल, व्हाइट हाउस की शर्तों पर क्यों चुप रही Modi Govt?

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, किसानों, पशुधन और कपड़ा क्षेत्र को कमजोर करता है। इस समझौते को जनसंपर्क का दिखावा बताते हुए खरगे ने सवाल उठाया कि क्या यह भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करता है। खरगे ने इस बात पर जोर दिया कि वक्तव्य में रूस से तेल खरीदना बंद करने की भारत की प्रतिबद्धता को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क हटाने की शर्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो उनके अनुसार भारत की संप्रभुता का हनन है। एक्स पर एक पोस्ट में, खरगे ने लिखा कि हमें बताया गया था कि भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में रूसी तेल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जबकि श्री ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से इसके विपरीत ट्वीट किया था। अब व्हाइट हाउस के

फैक्ट शीट में स्पष्ट रूप से रूसी संघ से तेल खरीदना बंद करने की भारत की प्रतिबद्धता को अतिरिक्त 25त टैरिफ हटाने की शर्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मोदी सरकार ने भारत की संप्रभुता के इस हनन पर सहमति जताई। क्यों? कांग्रेस पार्टी ने पहले ही उस कार्यकारी आदेश का खुलासा कर दिया था जिसके तहत भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तेल आयात के लिए अमेरिकी निगरानी में रखा गया था। खरगे ने कृषि को लेकर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि दालें और आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) चारा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी) और पशुओं के चारे के लिए लाल वार शामिल हैं, को चुपचाप समझौते में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके परिणामस्वरूप 2 करोड़ दुधारू किसान और देश की पशुधन आबादी प्रभावित हो सकती है। पोस्ट में लिखा था कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने हमारी कृषि को विदेशी वस्तुओं के लिए पूरी तरह खोल दिया है। अब हमें पता चल गया है कि मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में अतिरिक्त उत्पाद का वास्तव में क्या अर्थ था!

9 फरवरी को जारी व्हाइट हाउस के नए फैक्ट शीट में चुपचाप 'दालों' को शामिल कर लिया गया है, जो 6 फरवरी, 2026 को जारी भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य का हिस्सा नहीं था। संयुक्त वक्तव्य में भारत में लाल वार के आयात की उपयोगिता का उल्लेख किया गया था, लेकिन पशु आहार से संबंधित वह उपयोगिता अब 9 फरवरी, 2026 के व्हाइट हाउस फैक्ट शीट से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है, वस्त्र क्षेत्र में, खरगे ने आयात पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाने के लिए सरकार की आलोचना की, जबकि बांग्लादेश को अमेरिकी कपास पर शून्य शुल्क की पहुँच प्राप्त है, जिससे उनके अनुसार तिरुपुर और सूरत जैसे भारतीय वस्त्र केंद्रों को नुकसान हो रहा है।

स्वदेशी को बढ़ावा देने दिल्ली में जुटेंगे बड़े व्यापारी, केंद्र के इशारे पर शुरू हुई ये पहल

नई दिल्ली । देश में स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश से व्यापारी दिल्ली में जुटेंगे। एक मई से चार मई तक चलने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में पूरे देश में सभी प्रमुख सेक्टर में स्वदेशी को बढ़ावा देने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की जाएगी। व्यापारी संगठन कैट के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक माध्यमों और ई कॉमर्स के उपयोग के रास्ते भी तलाशे जाएंगे। भारत और यूरोपीय यूनियन और भारत-अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलने की असीम संभावना है।

केंद्र सरकार घरेलू निर्माण क्षेत्र को मजबूत कर इसके माध्यम से व्यापारियों, किसानों और कामगारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत के व्यापारिक परिदृश्य में ऐतिहासिक और तेज परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस समय देश का आंतरिक व्यापार सशक्त हुआ है, और वैश्विक बाजार भारतीय उत्पादों के लिए नए-नए अवसर खोल रहा है। ऐसे में इस अवसर का लाभ उठाने के लिए स्थानीय लोगों को आगे आना चाहिए। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और देश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छुएगी। व्यापारी संगठन कैट के नेता और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि यह महोत्सव अत्याधुनिक तकनीक से संचालित होगा।

विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग पवेलियन होंगे, जिससे व्यापारिक आगंतुकों को नए अवसर तलाशने में सुविधा होगी।

डिजिटल कियोस्क, एक विशेष मोबाइल ऐप के ज़रिए एआई असिस्टेंट, प्रगति मैदान का डिजिटल मैप और क्यूआर कोड आधारित प्रवेश व्यवस्था इस महोत्सव को अपनी तरह की अब तक की सबसे आधुनिक और उत्कृष्ट प्रदर्शनी बनाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस महोत्सव में केवल भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं का ही प्रदर्शन किया जाएगा, जो स्वदेशी की भावना को नई ऊर्जा देगा।

डीयू कॉलेज को बनाया मंडप और हॉस्टल को गेस्ट हाउस! बेटे की शादी के लिए प्रिंसिपल की मनमानी पर भड़के छात्र

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में सोमवार को छात्रों का आक्रोश उस समय खुलकर सामने आया, जब कॉलेज परिसर में प्राचार्य के पुत्र की शादी के आयोजन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज के खेल मैदान और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निजी उपयोग किया जा रहा है, जबकि सामान्य दिनों में इन्हीं सुविधाओं के इस्तेमाल पर छात्रों के लिए सख्त पाबंदियां लागू रहती हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज का खेल मैदान, जहां खेल गतिविधियों और वार्षिक 'खेलो हंसराज' टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना था, उसे निजी समारोह के लिए सजाया गया। इसके चलते प्रस्तावित खेल प्रतियोगिता को अचानक रद्द कर दिया गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि इस फैसले की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई

और मैदान को घेरकर निजी कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह भी मुद्दा उठाया कि कॉलेज का बॉयज हॉस्टल, जिसे बीते वर्ष आधारभूत ढांचे की खराब स्थिति बताकर रहने योग्य नहीं घोषित किया गया था, अब शादी में आए मेहमानों के ठहरने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। हॉस्टल खाली कराए जाने के बाद छात्रों को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भटकना पड़ा, लेकिन अब उसी भवन का निजी उपयोग छात्रों को अस्वीकार्य लग रहा है। छात्रों का आरोप है कि शादी की तैयारियों के चलते कॉलेज परिसर के कुछ हिस्सों में आवाजाही भी सीमित कर दी गई है और मुख्य प्रवेश मार्गों को बंद कर वैकल्पिक रास्तों से आने-जाने को कहा जा रहा है। इससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है। छात्र संगठनों ने इस पूरे प्रकरण को प्रशासन की दोहरी नीति करार देते हुए पारदर्शिता की मांग की है। उनका कहना है कि जहां छात्र आयोजनों को अनुमति देने में प्रशासन सख्ती दिखाता है, वहीं निजी कार्यक्रमों के लिए नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्रों से लिखित रूप में मांगें सौंपने को कहा है। छात्रों का कहना है कि यदि सार्वजनिक संसाधनों के निजी उपयोग पर रोक और निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

लिपोसक्शन सर्जरी से महिला की मौत के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, 6 महीने में एनएमसी को देना होगा फैसला

नई दिल्ली ।दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को निर्देश दिया है कि कथित मेडिकल लापरवाही से जुड़ी शिकायत को छह महीने के अंदर किसी निर्णय तक पहुंचाया जाए. यह मामला सिंगापुर में रहने वाली भारतीय महिला वी. अनीथा की मौत से जुड़ा है, जिन्हें सितंबर 2021 में लिपोसक्शन सर्जरी के बाद तबीयत बिगड़ने पर फरीदाबाद के एक अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट में मृतका की मां रंजकम इंद्रा विश्वनाथन ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की मौत कथित रूप से गलत तरीके से की गई लिपोसक्शन सर्जरी के कारण हुई, लेकिन कई साल तक शिकायत करने के बावजूद मेडिकल नियामकों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. अनीथा की सर्जरी दिल्ली के SDA स्थित डेजायर

क्लिनिक में डॉ. प्रशांत यादव द्वारा की गई थी. याचिका में कहा गया है कि सर्जरी मानक चिकित्सा नियमों के विपरीत की गई और बाद में कई संदिग्ध परिस्थितियां सामने आईं. दिल्ली हाई कोर्ट में सवाल उठाया गया कि तबीयत बिगड़ने पर अनीथा को नजदीकी बड़े अस्पताल जैसे AIIMS या सफदरजंग ले जाने के बजाय करीब 27 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के वेदांता अस्पताल क्यों ले जाया गया? जिस पर याचिका में फरीदाबाद अस्पताल के मेडिकल लीगल केस का हवाला देते हुए कहा गया कि दस्तावेजों में विरोधाभास है एक जगह मरीज को बेहोश बताया गया जबकि दूसरी जगह brought dead लिखा है. परिवार के मुताबिक उन्होंने FIR दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन मेडिकल लापरवाही के मामलों में पहले मेडिकल जांच जरूरी होने के कारण पुलिस ने मना कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया फरवरी 2022 में दिल्ली मेडिकल काउंसिल में शिकायत दी गई, पर लंबे समय तक कोई फैसला नहीं आया. उन्होंने एनएमसी का रुख किया. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पहले राज्य मेडिकल काउंसिल को ऐसे मामलों पर फैसला करना चाहिए, लेकिन यदि वह देरी करें तो एनएमसी को शिकायत लेकर छह महीने के भीतर निर्णय देना होगा.

दिल्ली सरकार का बेहतर शिक्षा को लेकर बड़ा कदम, सर्वोदय विद्यालय की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने राजधानी में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पश्चिमी दिल्ली के मानसरोवर गार्डन स्थित सर्वोदय विद्यालय की नवनिर्मित इमारत का भव्य उद्घाटन किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली के विभिन्न सरकारी स्कूलों में स्थापित की गईं 100 नई आईसीटी कंप्यूटर लैब का भी शुभारंभ किया. इन आईसीटी लैब को लाडली फाउंडेशन और AIF (अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन) के सहयोग से तैयार किया गया है. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, हर एक कंप्यूटर लैब में 20 आधुनिक कंप्यूटर लगाए गए हैं और हर कंप्यूटर के साथ अलग सीपीयू उपलब्ध कराया गया है, ताकि छात्र सही तरीके से तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकें. इन लैब्स का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है.

इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का वर्चुअल उद्घाटन भी किया. DIET शिक्षक प्रशिक्षण का एक अहम संस्थान होता है, जहां से प्रशिक्षित शिक्षक तैयार होते हैं. इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य शिक्षकों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है, ताकि बच्चों को अच्छी

शिक्षा मिल सके.

इस दौरान मौजूद रहे ये लोग

कार्यक्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मोती नगर के विधायक हरीश खुराना भी मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मीडिया को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने सर्वोदय विद्यालय में उस पुरानी कंप्यूटर लैब को दिखाया, जिसे लेकर पहले की सरकार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के दावे किया करती थी.

कार्यक्रम के दौरान क्या बोले शिक्षा मंत्री?

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पहले जिस कंप्यूटर लैब की बात की जाती थी, वहां हकीकत में एक ही सीपीयू से 10 कंप्यूटर चलाए जा रहे थे. उन्होंने कहा कि वह लैब सिर्फ नाम की थी, असल में पूरे कमरे में केवल एक ही कंप्यूटर सिस्टम मौजूद था. मंत्री ने मौके पर पुरानी लैब और नई लैब की तुलना भी दिखाई.

हर लैब में कम से कम 20 कंप्यूटर हैं- आशीष सूद

शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज शुरू की गई 100 नई कंप्यूटर लैब में हर लैब में कम से कम 20 कंप्यूटर हैं. हर कंप्यूटर के साथ अलग सीपीयू लगाया गया है. इससे छात्रों को सही मायनों में कंप्यूटर शिक्षा मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि अब जनता खुद दोनों लैब को देखकर समझ सकती है कि सचाई क्या है और असली बदलाव किसे कहते हैं.

नई सरकार ने किया ये दावा

गौरतलब है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से चर्चा में रही है.

नई सरकार का दावा है कि वह सिर्फ दावे नहीं, बल्कि ज़मीन पर काम करके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है. 100 नई आईसीटी लैब और नए स्कूल भवन इसी दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं.

वैश्विक ऑर्डर का रूझान भारत की ओर

2026 की शुरुआत में खड़ा विश्व एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर है जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी पुरानी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और शक्ति के ध्रुवीकरण के इस दौर में, वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका एक संतुलनकारी शक्ति से बढ़कर एक निर्णायक नेतृत्व की ओर बढ़ रही है। आज की विश्व व्यवस्था अब एकध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, रूस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने वैश्विक संस्थानों की सीमाओं को उजागर कर दिया है। दुनिया अब कई शक्ति केंद्रों में विभाजित हो रही है, जहाँ मध्यम शक्तियाँ अपनी स्वायत्तता की तलाश में हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं वर्तमान संकटों को सुलझाने में विफल दिख रही हैं, जिससे सुधारित बहुपक्षवाद की मांग तेज हुई है। इन सब विषमताओं के बीच भारत की अपनी आर्थिक सुदृढ़ीकरण और वैश्विक नेतृत्व का उभार भारत को विश्व नेता के रूप में सामने प्रस्तुत कर रहा है। भारत ने खुद को विकासशील और अल्पविकसित देशों के प्रतिनिधि के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। जनवरी 2026 से भारत ने ब्रिक्स की कमान संभाली है। भारत का लक्ष्य इस मंच को पश्चिम-विरोधी बनाने के बजाय एक समावेशी वैश्विक मंच के रूप में विकसित करना है। भारत की विदेश नीति अब केवल राष्ट्रीय हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है, जैसा कि कोविड-19 के दौरान वैक्सीन मैत्री और तुर्की-सीरिया भूकंप में ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से देखा गया। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक नेतृत्व के दावों को ठोस आधार प्रदान करती है। अनुमान है कि भारत जल्द ही जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत ने किसी भी गुट का हिस्सा बने बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी है। वह एक तरफ क्वाड के जरिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस और मध्य-पूर्व के

भारत ने दुनिया को दिखाया कि कैसे डिजिटल तकनीक का उपयोग वित्तीय समावेशन के लिए किया जा सकता है। अब इंडिया स्टैक कई विकासशील देशों के लिए एक रोल मॉडल है। 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता एक ऐसे समय में आई है जब दुनिया डी-डलर लाइजेशन (डॉलर पर निर्भरता कम करने) और वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों की बात कर रही है। ब्रिक्स के नए सदस्यों (जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई) के आने के बाद, भारत की भूमिका इन विविध हितों को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण है। ब्रिक्स पे भारत अपनी डिजिटल भुगतान तकनीक के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने का नेतृत्व कर रहा है।

देशों के साथ ऊर्जा और रणनीतिक संबंध भी मजबूत कर रहा है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई और आधार, आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है। कई देश भारत की इस तकनीक को अपना रहे हैं, जिससे भारत सॉफ्ट पावर के साथ-साथ टेक पावर के रूप में भी उभर रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद और अस्थिर पड़ोस (पाकिस्तान, म्यांमार) भारत की ऊर्जा को डायवर्ट करते हैं। वैश्विक अस्थिरता के बीच अपनी विशाल आबादी के लिए निरंतर और सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। वैश्विक नेतृत्व के लिए बुनियादी ढांचे और अनुसंधान में भारी निवेश की निरंतर आवश्यकता है। भारत अब नियम फालो करने वाला देश नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला राष्ट्र बन रहा है। 2026 का यह वर्ष भारत के लिए अपनी वैश्विक साख को और गहरा करने का स्वर्णिम अवसर है। जी20 क्षेत्र में दुनिया को एकजुट करने के लिए इस गठबंधन की शुरुआत हुई, जो पर्यावरण संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका को दर्शाता है। भारत ने 2023 की अपनी अध्यक्षता के दौरान ल20 की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत ने इसे केवल आर्थिक चर्चा का मंच न रखकर एक जन-आंदोलन बना दिया। अफ्रीकी संघ को सदस्यता मिलना भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत अफ्रीकी संघ को ल20 का स्थायी सदस्य बनाना थी। इससे भारत ने साबित किया कि वह ग्लोबल साउथ का वास्तविक नेता है। भारत ने दुनिया को दिखाया कि कैसे डिजिटल तकनीक का उपयोग वित्तीय समावेशन के लिए किया जा सकता है। अब इंडिया स्टैक कई विकासशील देशों के लिए एक रोल मॉडल है। 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता एक ऐसे समय में आई है जब दुनिया डी-डलर लाइजेशन (डॉलर पर निर्भरता कम करने) और वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों की बात कर रही है। ब्रिक्स के नए सदस्यों (जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई) के आने के बाद, भारत की भूमिका इन विविध हितों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स पे भारत अपनी डिजिटल भुगतान तकनीक के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने का नेतृत्व कर रहा है। ब्रिक्स के भीतर चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए भारत एक लोकतांत्रिक और पारदर्शी विकल्प पेश करता है, जिससे यह समूह केवल एक पश्चिम-विरोधी गुट बनने के बजाय एक विकास-केंद्रित मंच बना रहे। कुलमिलाकर भारत अब केवल मेज पर बैठने की मांग नहीं कर रहा, बल्कि वह अब एजेंडा तय कर रहा है। वैश्विक ऋण संकट हो या खाद्य सुरक्षा, दुनिया अब समाधान के लिए नई दिल्ली की ओर देखती है।

सम्पादकीय...

प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पर चर्चा 2026 का मनोवैज्ञानिक सारांश

परीक्षा पर चर्चा 2026 (नवें संस्करण) पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कुशल मनोवैज्ञानिक की भांति विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा किया उन्होंने सीधे परीक्षा तनाव पर चर्चा करने के बजाय छात्रों के जीवन व उनके क्षेत्र से संबंधित विभिन्न आयामों पर चर्चा किया जिससे छात्र उनसे सीधे जुड़ सके। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि *हर छात्र अव्दितीय है* उनकी अपनी क्षमता, विशेषता, जीवनशैली, सोचने समझने का ढंग अलग- अलग होता है इसलिए विद्यार्थियों का परीक्षा की तैयारी का तरीका अलग-अलग हो सकता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि अपनी परीक्षा की तैयारी अपने ढंग से करनी चाहिए, सभी के सुझाव को सुनना चाहिए किंतु *अपने तैयारी का पैटर्न अपने अनुभव के अनुसार तय करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीवन में ज्ञान एवं कौशल दोनों महत्वपूर्ण है एक के बिना दूसरे का काम चलने वाला नहीं है इसलिए अध्ययन एवं प्रशिक्षण दोनों जीवन में आवश्यक है। उन्होंने छात्रों से कहा कि हमें बीते हुए कल पर नहीं बल्कि अपने वर्तमान एवं भविष्य पर अधिक फोकस करके अपने विकास की तैयारी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा की प्रश्न-पत्र उन विद्यार्थियों को ही कठिन लगता है जो *पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी* न करके सिर्फ परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयारी करतें हैं। उन्होंने कहा कि *मन को मजबूत एवं स्वस्थ रखना* उतना ही महत्वपूर्ण है जितना के शरीर को स्वास्थ्य व मजबूत रखना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जीवन परीक्षा के लिए नहीं है बल्कि परीक्षा जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों को *परीक्षा को बोझ व मजबूरी के रूप में न लेकर जीवन के विकास के लिए आवश्यक मानकर तैयारी करना चाहिए*, जीवन में अंकों का उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना की हमारे जीवन में हमारे ज्ञान व कौशल का होता है। भूलने की समस्या पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विद्यार्थी *जितनी अधिक सलंग्नता के साथ अध्ययन करेगा भूलना उतना ही कम होगा।* छात्रों को लिखकर अभ्यास करने का सलाह दिया क्योंकि लिखकर सीखी गई विषयवस्तु का विस्मरण कम होता है। विद्यार्थियों को आपस में विषय पर चर्चा करना चाहिए *चर्चा के माध्यम से अधिगम मजबूत होता है* तथा संप्रत्यय की समझ स्पष्ट होती है। अभिभावकों को चाहिए कि वह बचे को उनकी रुचि क्षमता के अनुसार अवसर व संसाधन उपलब्ध करायें ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाना चाहिए कमजोरी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों को संदेश दिया है छात्रों को प्रश्न पत्र का अभ्यास पर बल देने के बजाय संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ने पर जोर देना चाहिए ताकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आए तो विद्यार्थी आसानी से हल कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि *समय व्यवस्थापन जीवन की हर अवस्था में महत्वपूर्ण होता है* छात्र जीवन में यह अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि समय व्यवस्थापन से न केवल श्रम व ऊर्जा की बचत होती है बल्कि सुव्यवस्थित विकास होता है।

लाल आतंक से मुक्ति की ओर बढ़ रहा देश

नक्सल को समास करने को लेकर जब रणनीति तैयार होनी शुरू हुई, तो उसके लिए पहली लाइन समन्वय की बनाई गई, ताकि इस अभियान को बल मिले। बीती 8 फरवरी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित एक विशेष कॉन्क्लेव के दौरान शाह ने माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की पुरजोर अपील की। भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क और मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करके बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत किया है, जिससे पहुंच, सुरक्षा प्रतिक्रिया और सामाजिक-आर्थिक एकीकरण में सुधार हुआ है। मई 2014 से अगस्त 2025 तक, केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, जबकि कुल 17,589 किलोमीटर की परियोजनाओं को 20,815 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है। इन सबके बीच नक्सलवाद के खत्म होने के बाद विकास की जिस बुनियाद को जमीन पर उतरना है, वह बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वैसे सरेंडर नक्सलियों की है जो सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण किए हैं। उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़े रखना बड़ी चुनौती है। इस जगह पर शासकीय कमजोरी या प्रशासनिक ढांचे की लचर व्यवस्था का कोई भी छाप दिखा तो यह इस अभियान को फेल करने की बड़ी वजह बन सकता है। इसमें सबसे जरूरी है आम सुविधाओं का विस्तार और जो लोग सरकार की व्यवस्था पर भरोसा करके आए हैं, उसे भरोसे पर कायम रहने के सरकार के वैसे निर्णय जो सिर्फ विकास के लिए जाने जाते हैं, सबसे बड़ी चुनौती हैं।

जिस तरीके से पूरे देश में नक्सली के खिलाफ अभियान चलाया गया है, उससे एक बात है कि केंद्र की मोदी सरकार पूर्ण दृढ़ संकल्प और शपथ के जिस पथ को लेकर चल रही थी, उसमें एक मजबूत रणनीति जीत अब दिखने लगी है। केंद्र सरकार ने इस साल 31 मार्च तक लाल आतंक को खत्म करने की समय सीमा तय कर रखी है। जो पूरी होती दिखने लगी है। देश का 90 प्रतिशत क्षेत्र पहले ही नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुई नक्सलवाद की समस्या ने दशकों तक लाखों निर्दोष लोगों और सुरक्षाकर्मियों की जान ली और कई क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक ठोस और प्रभावी रणनीति अपनाई। पिछले 11 वर्षों में, केंद्र सरकार की समन्वित, बहुआयामी रणनीति, जिसमें सुनियोजित सुरक्षा अभियान, अभूतपूर्व अवसंरचना विकास, वित्तीय दबाव, तीव्र विकास और एक आकर्षक आत्मसमर्पण नीति शामिल है, ने वामपंथी उग्रवाद को 2014 में 126 जिलों से घटाकर 2025 में मात्र 11 जिलों तक सीमित कर दिया है, जिनमें से केवल तीन ही ÷सबसे अधिक प्रभावित ÷बचे हैं, जो लाल गलियारे के लगभग खात्मे का संकेत है। अकेले साल 2025 में, 317 नक्सलियों शीर्ष नेतृत्व सहित को मार गिराया गया, 800 से अधिक को गिरफ्तार किया गया और लगभग 2,000 ने आत्मसमर्पण किया, जिससे नक्सलियों को अब तक की सबसे बड़ी क्षति मिली और मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत की ओर तेज़ी से प्रगति हुई। छत्तीसगढ़ में सबसे यादा बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित है। इसमें सात जिले शामिल हैं। ये जिले महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ सीमा साझा करते हैं, और लंबे समय से इसे माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ माने जाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान तेज हुए हैं, जिससे नक्सलवाद पर तगड़ा प्रहार हुआ है। छत्तीसगढ़ में साल 2024 से अब तक सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशवा राव उर्फ बसवराजू जैसे टॉप नक्सल लीडर सहित 500 से अधिक नक्सलियों को फोर्स ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ में 23 माओवादी मारे जा चुके हैं। तीन जनवरी को, बस्तर क्षेत्र में दो मुठभेड़ में कुल 14 माओवादी मारे गए थे। नक्सलियों की आत्मसमर्पण को लेकर के जिस तरह से संख्या बढ़ी है, उससे एक बात साफ है कि नक्सलियों के भीतर इस बात का भय बैठ गया है, कि 31 मार्च तक आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो सरकार किसी तरह के समझौते के मूड में अब नहीं है। इसका परिणाम भी दिखा है। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे माओवादी कमांडर जो यहां रहे वे सभी मारे गए हैं। हिड़मा से लेकर जिन लोगों को भी छत्तीसगढ़ में कमान दी गई थी, या तो वह राय छोड़कर चले गए या फिर न्यूट्रलाइज हुए हैं। बचे हुए कैडर के पास अब इतनी क्षमता नहीं बची है, कि वो नक्सल अभियान को आगे लेकर चल सकें। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए नेशनल पार्क का 2799 वर्ग किलोमीटर का इलाका सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर इलाका घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा है। माओवादी इसे अपने कॉरिडोर के रूप में उपयोग करते थे, यह भी कहा जा सकता है, कि यह इलाका नक्सलियों का सबसे अभेद दुर्ग वाला इलाका रहा है। कभी नक्सलियों के अभेद किले के रूप में जाने जाने वाला नेशनल पार्क पहले एनकाउंटर जोन बनता जा रहा है। अब सुरक्षाबलों के कैंप बन जाने के बाद यहां से लाल आतंक के पैर उखड़ने लगे हैं। साल 2025 के बाद जिस नक्सल अभियान को चलाया गया उसमें यह बात तय की गई, कि मानसून के मौसम में भी इस अभियान को नहीं रोका जाएगा। नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर चलाए जा रहे अभियान में हेलीकॉप्टर मिल जाने के बाद सुरक्षाबलों को बहुत सहूलियत मिल गई। मानसून के मौसम में हेलीकॉप्टर के आ जाने के बाद मॉनिटरिंग भी तेज हो गई। नेशनल पार्क इलाके में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर फोर्स तैनात होने साथ ही सुरक्षा बलों द्वारा कैंप खोल दिए जाने के बाद फोर्स की गतिविधियां तेज हो गई। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली एनकाउंटर और उसमें जिस तरीके के नक्सली मारे गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान को चलाने वाले बड़े नक्सली बचे ही नहीं हैं। जो भी नक्सली छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन को दिशा देते थे, उसके लिए रणनीति बनाते थे, उन तमाम नक्सलियों को या तो न्यूट्रलाइज किया गया या फिर कई ऐसे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सली संगठन के बचे कैडर को और संगठन को दिशा देने वाले लोगों की जगह ही नहीं बची है। अब पूरा नक्सली संगठन ही नेतृत्व विहीन हो चुका है। यह एक बड़ी वजह है कि 60 दिनों के भीतर इसे पूरे तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने एनआईए में एक समर्पित विभाग बनाकर नक्सलियों के वित्तपोषण पर प्रभावी ढंग से लगाम लगा दी है। इस विभाग ने 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जबकि रायों ने भी 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है और प्रवर्तन निदेशालय ने 12 करोड़ रुपये कुर्क किए हैं। इस एक साथ की गई कार्रवाई से शहरी नक्सलियों को गंभीर नैतिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंची है और उनके सूचना युद्ध नेटवर्क पर नियंत्रण और भी कड़ा हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के नक्सल मुक्त करने को लेकर बनी रणनीति में रायों के बीच समन्वय एक एक बहुत मजबूत आधार बना। रायों के बीच आपसी तालमेल नहीं होना नक्सल के सफल होने का एक कारण होता था। नक्सल को समास करने को लेकर जब रणनीति तैयार होनी शुरू हुई, तो उसके लिए पहली लाइन समन्वय की बनाई गई, ताकि इस अभियान को बल मिले। बीती 8 फरवरी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित एक विशेष कॉन्क्लेव के दौरान शाह ने माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की पुरजोर अपील की। भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क और मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करके बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत किया है, जिससे पहुंच, सुरक्षा प्रतिक्रिया और सामाजिक-आर्थिक एकीकरण में सुधार हुआ है। मई 2014 से अगस्त 2025 तक, केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, जबकि कुल 17,589 किलोमीटर की परियोजनाओं को 20,815 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है। इन सबके बीच नक्सलवाद के खत्म होने के बाद विकास की जिस बुनियाद को जमीन पर उतरना है, वह बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वैसे सरेंडर नक्सलियों की है जो सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण किए हैं। उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़े रखना बड़ी चुनौती है। इस जगह पर शासकीय कमजोरी या प्रशासनिक ढांचे की लचर व्यवस्था का कोई भी छाप दिखा तो यह इस अभियान को फेल करने की बड़ी वजह बन सकता है। इसमें सबसे जरूरी है आम सुविधाओं का विस्तार और जो लोग सरकार की व्यवस्था पर भरोसा करके आए हैं, उसे भरोसे पर कायम रहने के सरकार के वैसे निर्णय जो सिर्फ विकास के लिए जाने जाते हैं, सबसे बड़ी चुनौती हैं। वास्तव में, देश से नक्सलवाद का खत्म होना विकासवाद की उस अवधारणा की पहली कुंजी है, जिससे भारत पूरे विश्व के फलक पर एकजुट होकर सिर्फ विकास की लड़ाई लड़ेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कनन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साय पीतलबला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

मेरा युवा भारत बजट क्विज 2026 का आयोजन, युवाओं को बजट से जोड़ने की पहल

कुशीनगर।

मेरा युवा भारत (युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार) के नेतृत्व में पडरौना ब्लॉक स्थित योद्धा बाबा एसटीएस इंटरमीडिएट कॉलेज, पिपरा धर्मपुर में मेरा युवा भारत बजट क्विज 2026 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम युवाओं को केंद्रीय बजट 2026 से जोड़ने, उनकी आर्थिक एवं नीतिगत समझ को सशक्त बनाने तथा विकसित भारत@2047 के विज़न में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला युवा अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के प्रथम चरण में एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। क्विज में सफल प्रतिभागियों को द्वितीय चरण में चयनित आठ विषयों पर निबंध

लेखन का अवसर मिलेगा। ये विषय बजट, युवा सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा, नवाचार, आत्मनिर्भर भारत एवं राष्ट्रीय विकास से संबंधित होंगे। निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद में शामिल होने का विशेष अवसर प्राप्त होगा, जिसमें युवा अपने विचार सीधे देश के सर्वोच्च नेतृत्व के समक्ष रख सकेंगे। पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पारितोष दुबे ने युवाओं को जानकारी देते हुए बताया कि "मेरा युवा भारत बजट क्विज 2026 का आयोजन दिनांक 3 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देशभर के युवा मेरा युवा भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर इस क्विज प्रतियोगिता अभियान में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, रचनात्मक सोच तथा राष्ट्रीय नीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर मेरा युवा भारत एवं विद्यालय प्रबंधन की ओर से अवधेश सिंह द्वारा युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान से जुड़ने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। अधिक जानकारी एवं सहभागिता हेतु युवा www.mybharat.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अध्यापकगण सुशील सिंह, आलोक सिंह, अंकित सिंह, गुलाब यादव, संजय तथा सोनू तिवारी सहित बड़ी संख्या में युवाओं की गरिमामयी उपस्थिति रही।

गायत्री नगर वार्ड में सीसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ

पड़रौना नगर। नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के प्रयासों से गायत्री नगर वार्ड अंतर्गत बलूचह्वां में सीसी रोड निर्माण कार्य का विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया गया। निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के हवाले से बताया गया कि सीसी रोड निर्माण से क्षेत्र को जलभराव, कीचड़ और आवागमन की समस्याओं से स्थायी राहत मिलेगी तथा नागरिकों को सुगम व सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। यह कार्य नगर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय नागरिकों ने विकास कार्य के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नगरपालिका प्रशासन के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम में रामरतन गुप्ता, कैलाश शर्मा, अवधेश चौरसिया, भोला मिश्रा, तुलसी शर्मा, रामदुलारे गुप्ता, ओमप्रकाश गुप्ता, आलोक गुप्ता, संतोष शर्मा, राकेश गुप्ता, गुल्लू मद्धेशिया, सत्री मिश्रा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

श्रमिक अधिकार जागरूकता अभियान में योजनाओं की जानकारी, समस्याओं के समाधान का आश्वासन

दुदही, कुशीनगर ।

ब्लॉक सभागार दुदही में एक्शन एड एसोसिएशन और श्रमिक सुविधा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में श्रमिक अधिकार जागरूकता अभियान का आयोजन खण्ड विकास अधिकारी के.के. राय की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में असंगठित श्रमिकों ने सरकारी योजनाओं, रोजगार और स्थानीय समस्याओं को लेकर सीधे खण्ड विकास अधिकारी से संवाद किया। के.के. राय ने श्रमिक सुविधा केंद्र की सराहना करते हुए विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि श्रमिक प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे उनसे मिल सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्याय मित्रों ने 22 फरवरी को दीवानी न्यायालय में आयोजित होने वाले वृहद विधिक जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी, जिसमें 44 विभागों की योजनाओं से लाभ दिलाया जाएगा।

कार्यक्रम में श्रमिक पंजीयन, ई-श्रम, नवीनीकरण, महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड लाइन और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी गई। श्रमिकों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया गया। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे।

बड़ी गंडक पर प्रस्तावित पक्के पुल के लिए मिट्टी परीक्षण शुरू

नेबुआ नौरंगिया (कुशीनगर)।

खड्डा तहसील क्षेत्र में बड़ी गंडक नदी पर प्रस्तावित पक्के पुल के निर्माण की दिशा में अहम प्रगति हुई है। भैंसहा घाट पर ठेकर नंबर तीन के पास मशीन द्वारा मिट्टी परीक्षण (सॉइल टेस्टिंग) का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस पुल के निर्माण पर लगभग 6 अरब 49 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

सेतु निगम द्वारा पुल निर्माण का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है। मिट्टी परीक्षण पूर्ण होने के बाद पुल के डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्य शुरू होने से रेतां क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि वर्षों पुरानी पक्के पुल की मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। आजादी के बाद से भैंसहा, मरिचह्वा, हरिहरपुर, नारायणपुर, शिवपुर, सोहगीबरवा, बसही, शिकरपुर सहित दर्जनों गांवों के लगभग 50 हजार लोग आवागमन की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। बरसात में नाव और पीपा पुल ही सहारा होते थे, जो पानी बढ़ने पर बह जाया करते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि

पुल बनने से खड्डा तहसील, जिला मुख्यालय तक पहुंच आसान होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीणों ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

यूजीसी एक्ट लागू कराने को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित

कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव स्थित भगवान बुद्ध एवं भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थल के समीप मंगलवार को यूजीसी एक्ट को लागू कराने के उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व युवा बसपा नेता रामानंद गौतम ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बुद्ध, भारतीय संविधान और डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन-अर्चन से हुई। इसके बाद वक्ताओं ने यूजीसी एक्ट के महत्व और इसके सामाजिक प्रभावों पर अपने विचार रखे। बसपा जिला महासचिव मनोज कुमार गौतम ने कहा कि यूजीसी एक्ट समाज में समानता, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा तथा यह संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। पडरौना विधानसभा महासचिव लालधर प्रसाद ने वन नेशन, वन एजुकेशन पर चर्चा करते हुए यूजीसी एक्ट को जनहित में आवश्यक बताया। कार्यक्रम आयोजक व खड्डा विधानसभा महासचिव रामानंद गौतम ने कहा कि यूजीसी एक्ट लागू होने से शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने में मदद मिलेगी। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में सरकार से यूजीसी एक्ट को शीघ्र लागू करने की मांग की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर गोलू आजाद, हरिलाल कुशवाहा, अवधेश कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

डिजिटल सुरक्षा पर प्रशासन का ज़ोर, 'सुरक्षित इंटरनेट दिवस-2026' पर जिले में जागरूकता कार्यशाला

देवरिया।

डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर खतरों और तकनीक के विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर जिले में प्रशासनिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की पहल की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस-2026 के अवसर पर विकास भवन स्थित गांधी सभागार में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित प्रयोग पर विशेष फोकस रहा। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने डिजिटल तकनीक के बढ़ते प्रभाव की ओर संकेत करते हुए कहा कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक साधन विकास को गति देने वाले हैं, लेकिन इनके दुरुपयोग से गंभीर सामाजिक और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ मशीनों द्वारा मानव जैसी सोच और निर्णय क्षमता विकसित करना है, जिसका उपयोग तभी लाभकारी है जब वह सुरक्षित, जिम्मेदार और नियमों के दायरे में किया जाए। इस वर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस की थीम Smart Tech, Safe Choices रखी गई, जिसका आशय है तकनीक का समझदारी से चयन और सुरक्षित निर्णय। कार्यक्रम के दौरान जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कृष्णानंद यादव ने साइबर सुरक्षा, साइबर हाइजीन यानी डिजिटल स्वच्छता, ऑनलाइन धोखाधड़ी के तौर-तरीकों और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनजान लिंक, संदिग्ध कॉल और फर्जी संदेशों से दूरी ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। साइबर सेल के शिवमंगल यादव ने साइबर अपराधों के व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया कि ऑनलाइन ठगी, डेटा चोरी और पहचान के दुरुपयोग जैसी घटनाओं से कैसे सतर्क रहा जाए तथा ऐसी किसी भी स्थिति में साइबर हेल्पलाइन और आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना क्यों आवश्यक है। मुख्य विकास

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग और ऑनलाइन ठगी से बचाव पर सीडीओ ने जताई गंभीर चिंता

अधिकारी ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि डिजिटल रूप से सुरक्षित समाज की दिशा में ठोस कदम हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा जताई कि वे स्वयं जागरूक बनें और आमजन तक सही जानकारी पहुँचाने में भूमिका निभाएं। कार्यशाला का उद्देश्य शासकीय कार्मिकों और नागरिकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना तथा इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना रहा। कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह, ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक राजीव, जिला कार्यक्रम अधिकारी आदीश मिश्रा, डीसी एनआरएलएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

बढ़त के साथ खुला घरेलू शेयर बाजार; सेंसेक्स 247 अंक चढ़ा, निफ्टी 25900 के पार

नई दिल्ली । हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को भारतीय बाजार बढ़त के साथ खुला। एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुझानों और विदेशी निधियों के निरंतर प्रवाह के चलते, इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने मंगलवार को लगातार तीसरे सत्र में अपनी बढ़त जारी रखी।

विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी बाजारों में मजबूती और नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच अंतरिम व्यापार ढांचे को लेकर आशावाद से निवेशकों का मनोबल बढ़ रहा है। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 90.77 पर आ गया। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 247.01 अंक या 0.29 प्रतिशत चढ़कर 84,312.76 पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 80.25 अंक या 0.31 प्रतिशत बढ़कर 25,947.55 पर पहुंच गया।

सेंसेक्स की कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में इटरनल, टाइटन, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सन फार्मास्यूटिकल्स, पावरग्रिड, मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और टाटा स्टील लाभ कमाने वाले शेयर रहे। दूसरी ओर, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एशियन पेंट्स, इंडिगो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक पिछड़ने वालों में शामिल थे।

एशियाई बाजारों में दिखी तेजी

एशियाई बाजारों में, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, हांगकांग का हैंग सेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक उच्च स्तर पर कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक स्थिर बना हुआ है। सोमवार को रात भर के कारोबार में अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी देखी गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम रिसर्च के प्रमुख देवरश वकील ने कहा कि जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की शानदार चुनावी जीत और तकनीकी शेयरों में सुधार को लेकर आशावाद के चलते सोमवार को वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी आई, जबकि चीन द्वारा वित्तीय संस्थानों को अमेरिकी बॉन्ड में निवेश सीमित करने की सलाह देने की खबरों के बीच डॉलर में गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि निवेशक अब बुधवार को जारी होने वाले जनवरी के रोजगार आंकड़ों और शुक्रवार को जारी होने वाले सीपीआई मुद्रास्फीति आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। ये आंकड़े 2026 के शेष भाग के लिए फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

ब्रेंट क्रूड का भाव गिरकर 68.85 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.28 प्रतिशत गिरकर 68.85 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गया। इस बीच, एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 2,254.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। सोमवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 485.35 अंक बढ़कर 84,065.75 पर बंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 173.60 अंक बढ़कर 25,867.30 पर बंद हुआ।

जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश घटा

नई दिल्ली । इक्विटी म्यूचुअल फंडों में जनवरी में निवेश की रफ्तार कुछ धीमी रही। उद्योग संगठन एएमएफआई के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में शुद्ध निवेश 24,028 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले महीने की तुलना में 14 प्रतिशत कम है। यह लगातार दूसरा महीना रहा जब इक्विटी फंडों में निवेश घटा। कमजोर बाजार परिस्थितियों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों का रुख सतर्क बना रहा।

उद्योग की कुल परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी जारी

हालांकि, इक्विटी में सुस्ती के बावजूद म्यूचुअल फंड उद्योग की कुल परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी जारी रही। जनवरी में कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 81.01 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह दिसंबर में 80.23 लाख करोड़ रुपये था। पूरे उद्योग में जनवरी के दौरान 1.56 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज किया गया। दिसंबर में 66,591 करोड़ रुपये के शुद्ध निकासी के बाद मजबूत वापसी को दर्शाता है, जिसे विभिन्न श्रेणियों में निवेश का समर्थन मिला। आंकड़ों के अनुसार, इक्विटी फंडों में निवेश नवंबर में 29,911 करोड़ रुपये और दिसंबर में 28,054 करोड़ रुपये था, जो जनवरी में घटा, हालांकि यह अक्तूबर के 24,690 करोड़ रुपये से अधिक बना रहा। इक्विटी योजनाओं में फ्लेक्सी-कैप फंड सबसे आगे रहे, जिनमें 7,672 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया। इसके बाद मिड-कैप फंडों में 3,185 करोड़ रुपये और लार्ज एवं मिड-कैप फंडों में 3,182 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज किया गया। लार्ज-कैप फंडों में 2,005 करोड़ रुपये और स्मॉल-कैप फंडों में 2,942 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। वहीं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में 593.69 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी देखी गई, जिसे मुनाफावसूली और कर-संबंधी समायोजन से जोड़ा जा रहा है। इस बीच, गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में निवेश में तेज उछाल आया। जनवरी में गोल्ड ETF में 24,040 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो दिसंबर के 11,647 करोड़ रुपये से दोगुने से भी अधिक है। डेट म्यूचुअल फंडों ने भी वापसी करते हुए जनवरी में 74,827 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज किया, जबकि दिसंबर में इन फंडों से 1.32 लाख करोड़ रुपये की भारी निकासी हुई थी।

सेबी की सख्ती: एनसीडीईएक्स और एमएसई की डेरिवेटिव्स बाजार में एंट्री पर रोक, नियामक ने कहा- हवा में महल न बनाएं

नई दिल्ली ।

भारतीय शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बेतहाशा बढ़ते क्रेज और खुदरा निवेशकों के जोखिम को देखते हुए बाजार नियामक सेबी ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। सेबी ने देश के दो उभरते एक्सचेंजों- नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) और मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसई) की इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। नियामक ने दो टूक शब्दों में इन एक्सचेंजों को सलाह दी है कि वे डेरिवेटिव्स का आकर्षक बाजार शुरू करने से पहले अपने कैश मार्केट (शेयर ट्रेडिंग) के बिजनेस को मजबूत करें। सेबी का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बिना मजबूत आधार के डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को बढ़ावा न मिले। सूत्रों के मुताबिक, सेबी ने साफ कहा है कि किसी भी नए एक्सचेंज को डेरिवेटिव्स लॉन्च करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वे एक लिक्विड (तरल) कैश मार्केट स्थापित नहीं कर लेते। छह महीने का नियम- सेबी चाहता है कि कैश इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स के लॉन्च के बीच कम से कम छह महीने का अंतर हो। प्राइस डिस्कवरी-

एक्सचेंजों को यह साबित करना होगा कि उनके कैश मार्केट में पर्याप्त भागीदारी, लिक्विडिटी और सटीक प्राइस डिस्कवरी हो रही है। नियामक नहीं चाहता कि नए खिलाड़ी बिना किसी ठोस आधार के डेरिवेटिव ट्रेडिंग को और हवा दें। टेक्नोलॉजी अपग्रेड- सेबी ने दोनों एक्सचेंजों को इक्विटी सेगमेंट में उतरने से पहले अपनी तकनीक को अपग्रेड करने का भी निर्देश दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत का इक्विटी डेरिवेटिव बाजार आसमान छू रहा है।

आंकड़ों के मुताबिक, भारत में डेरिवेटिव्स का प्रीमियम अब कैश मार्केट के आकार का लगभग दोगुना हो चुका है, जबकि प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात महज 2फीसदी से 3फीसदी है।

सरकार और सेबी इस असंतुलन को लेकर चिंतित हैं। हाल ही में सरकार ने ट्रेडिंग वॉल्यूम कम करने के लिए ट्रांजेक्शन टैक्स भी बढ़ाया था। अध्ययनों से पता चला है कि एफएंडओ में 90फीसदी खुदरा निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है, जो नियामक की सतर्कता का एक बड़ा कारण है। एनसीडीईएक्स (जो मुख्य रूप से कृषि कमोडिटीज में ट्रेड करता है) और एमएसई (जो करेंसी डेरिवेटिव्स में सक्रिय है) दोनों ने अपने कारोबार में विविधता लाने के लिए सेबी से मंजूरी मांगी थी। इन दोनों एक्सचेंजों ने इक्विटी विस्तार के लिए हाल ही में भारी-भरकम फंड जुटाया था। एनसीडीईएक्स- 2025 में एक्सचेंज ने सिटाडेल सिक्योरिटीज और टॉवर रिसर्च जैसी दिग्गज ग्लोबल फर्मों सहित 61 निवेशकों से 7.7 अरब रुपये (85 मिलियन) जुटाए थे।

एमएसई- इसने पीक एक्सवी वेंचर पार्टनर्स और ग्रो व जीरोधा जैसी ब्रोकरेज फर्मों से 12 अरब रुपये जुटाए थे। सेबी के इस निर्देश के बाद इन एक्सचेंजों की विस्तार योजनाओं को बड़ा झटका लग सकता है।

एनएसई का दबदबा कायम रहेगा

सेबी के इस कदम का सीधा मतलब है कि भारतीय डेरिवेटिव्स बाजार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एकछत्र राज फिलहाल जारी रहेगा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजों के डेटा के अनुसार, दुनिया भर में ट्रेड होने वाले इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में एनएसई की हिस्सेदारी 70फीसदी से अधिक है।

नए खिलाड़ियों के लिए एफएंडओ बाजार में प्रवेश की बाधाएं बढ़ाकर सेबी ने साफ कर दिया है कि वह बाजार की सुरक्षा और स्थिरता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, भले ही इसके लिए प्रतिस्पर्धा को कुछ समय के लिए रोकना पड़े।

एयरलाइन का पायलट-क्रू बफर बढ़ा, सरकार को 10 फरवरी के बाद उड़ानें सुचारू रहने की उम्मीद

नई दिल्ली । देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने दिसंबर में शून्य से फरवरी तक अपना क्रू बफर बढ़ाकर 3त्र कर लिया है। साथ ही पायलट-टू-एयरक्राफ्ट अनुपात भी मजबूत किया है। इन सुधारों के बाद सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को उम्मीद है कि 10 फरवरी को पायलट ड्यूटी और विश्राम से जुड़े नियमों (स्नझ्ञरु) पर दी गई अस्थायी छूट खत्म होने के बावजूद उड़ानों में न्यूनतम ही बाधा आएगी।

दिसंबर में देश ने देखा इंडिगो संकट

दिसंबर में एफडीटीएल मानकों के उल्लंघन से इंडिगो की परिचालन व्यवस्था चरमरा गई थी।

उस दौरान एयरलाइन को 5,000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं और विमानन नियामक डिजिसिए ने रिकॉर्ड 22.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। हालात संभालने के लिए डिजिसिए ने 6 दिसंबर को रात की ड्यूटी से जुड़े नियमों में 10 फरवरी तक अस्थायी छूट दी थी।

प्रति विमान पायटल क्रू सेट की संख्या बढ़ी

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अब एयरलाइन ने रोस्टरिंग योजनाओं में सुधार करते हुए प्रति विमान पायलट

क्रू सेट की संख्या बढ़ा दी है। फरवरी के रोस्टर में यह औसतन 7.2 क्रू सेट प्रति विमान तक पहुंच गई है, जो जनवरी में 7.1 थी। दिसंबर के संकट के समय यह संख्या छह से भी कम थी। क्रू सेट का मतलब है हर विमान के लिए उपलब्ध पूर्ण पायलट टीमों की संख्या। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिसंबर 2025 में जहां क्रू बफर शून्य था, वह फरवरी में बढ़कर 3त्र हो गया है, जबकि स्टैंडबाय क्रू की न्यूनतम सीमा 15त्र तक कर दी गई है। इससे बीमारी, आकस्मिक अवकाश या शेड्यूल में गड़बड़ी की स्थिति में उड़ानों को संभालने की क्षमता बढ़ी है।

इन आंकड़ों का अकलन नए स्नष्ठञ्जरुनियमों के संदर्भ में जरूरी

हालांकि, विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि इन आंकड़ों का आकलन नए एफडीटीएल नियमों के संदर्भ में जरूरी है। विशेषज्ञ कैप्टन मोहन रंगनाथन के अनुसार, सुचारू संचालन के लिए प्रति विमान कम से कम सात क्रू सेट होना अनिवार्य है। अगर छ्वत्रष्ट को दिए गए आंकड़े वास्तव में उड़ान भर रहे विमानों के अनुरूप हैं, तो व्यवधान की आशंका नहीं होगी।

क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 8 दिसंबर 2025 तक इंडिगो के पास 5,085 पायलट और करीब 350 सक्रिय विमान थे।

जनवरी में एयरलाइन ने 100 ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर नियुक्त किए और आने वाले महीनों में नियमित प्रशिक्षण की योजना बनाई है।

वहीं, अगले छह महीनों में कुछ पायलटों के इस्तीफे और सेवानिवृत्ति भी अनुमानित हैं।

मंत्रालय की समीक्षा में क्या आया सामने?

मंत्रालय की समीक्षा में यह भी सामने आया है कि जनवरी में हुई उड़ान रद्दियां मुख्य रूप से खराब मौसम, एयरस्पेस प्रतिबंध और अन्य परिचालन कारणों से थीं, न कि पायलट ड्यूटी नियमों के उल्लंघन से। 15 से 31 जनवरी के बीच इंडिगो ने लगभग 90त्र निर्धारित सेवाएं संचालित कीं और कुल 284 उड़ानें रद्द हुईं। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अध्यक्ष सीएस रंधावा ने कहा कि मौजूदा ऑपरेशनल फ्लीट के हिसाब से इंडिगो के पास पर्याप्त पायलट हैं और 10 फरवरी की समयसीमा के बाद उड़ानों के रद्द होने की कोई बड़ी वजह नहीं दिखती।

घर बनवाना हुआ महंगा, दिल्ली से मुंबई तक बढ़ा सरिया का भाव

नेशनल डेस्क । अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों की जेब पर अब महंगाई की मार पड़ने वाली है। जो लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि निर्माण सामग्री के दाम और गिरेंगे, उनके लिए बुरी खबर है। घर की मजबूती की बुनियाद माना जाने वाला सरिया अब सस्ता होने के बजाय तेजी से महंगा होने लगा है। पिछले कुछ हफ्तों में इसके भाव में जो उछाल आया है, उसने घर बनाने की कुल लागत को अचानक बढ़ा दिया है। पिछले साल के अंत तक सरिये की कीमतों में लगातार नरमी देखी जा रही थी, जिससे आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद जगी थी। लेकिन जनवरी बीतते-बीतते बाजार का रुख पूरी तरह बदल गया। नवंबर के मुकाबले अब सरिये की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। जानकारों का मानना है कि निर्माण कार्यों में तेजी और बाजार की बदलती स्थितियों ने लोहे के इस भाव को फिर से हवा दे दी है। देश के बड़े शहरों में सरिये के दाम में प्रति टन हजारों रुपये का इजाफा हुआ है। दिल्ली जैसे शहर में यह 48,900 रुपये प्रति मीट्रिक टन के करीब पहुंच गया है। वहीं, मुंबई, चेन्नई और रायपुर जैसे औद्योगिक केंद्रों में तो नवंबर के मुकाबले 6,000 से 6,800 रुपये तक की भारी बढ़त दर्ज की गई है। अगर आप भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं, तो पुराने रेट के भरोसे न रहें। सरिये के दाम हर दिन बदलते हैं। आप आयरनमार्ट जैसी वेबसाइटों पर जाकर अपने शहर का ताजा भाव चेक कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि वहां दिखाई गई कीमत में 18फीसदी जीएसटी अलग से जुड़ेगा, जिससे फाइनल बिल थोड़ा और बढ़ जाएगा।